के. एन. मेहरा

बनाम

राजस्थान राज्य

[जगन्नाथदास, जाफर इमाम और गोविंदा मेनन न्यायमूर्ति गण]

विमान, की चोरी - प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त - निहित सहमति - बेईमान इरादा - अस्थायी प्रतिधारण - चोरी और लार्सेनी, भेद - भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम XLTI), धारा 23, 24, 378।

भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार: "जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को इस तरह से लेने के लिए स्थानांतरित करता है, उसे चोरी करना कहा जाता है"।

पी और अपीलकर्ता भारतीय वायु सेना अकादमी, जोधपुर में प्रशिक्षण पर कैडेट थे, लेकिन पी को कदाचार के आधार पर छुट्टी दे दी गई थी, और घटना के दिन अपीलकर्ता को अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में डकोटा में एक स्थानीय उड़ान के लिए जाना था। एक नेविगेटर के रूप में. पी, जो उड़ना जानता था, की सहायता से उसने एक अन्य प्रकार का विमान हार्वर्ड एच. टी. 822 उड़ाया बिना अनुमति के और उसी दिन वे पाकिस्तान में एक स्थान पर जबरन उतरे। कुछ दिनों बाद उन्होंने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से संपर्क किया और भारत आते समय उन्हें जोधपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और विमान की चोरी का मुकदमा चलाया गया। अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि प्रशिक्षण के तहत एक कैडेट के रूप में वह उड़ान पर एक विमान लेने का हकदार था और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अर्थ के तहत विमान को "स्थानांतरित" करने के लिए एक निहित सहमति थी, और परिणामस्वरूप कोई बेईमानी का इरादा नहीं हो सकता, उड़ान शुरू होने के समय ऐसा कोई इरादा तो हो ही नहीं सकता, जिसे चोरी माना जाए। यह पाया गया कि जिस उद्देश्य से उड़ान भरी गई थी वह पाकिस्तान जाकर वहां रोजगार की तलाश करना था।

यह माना गया कि चूंकि उड़ान अनधिकृत थी, इसलिए कोई सहमति नहीं हो सकती थी और चूंकि यह मामले की परिस्थितियों में शुरू में गैरकानूनी था, और अपीलकर्ता ने अपने स्वयं

के उद्देश्यों के लिए विमान का अस्थायी उपयोग प्राप्त किया और सरकार को इसके उपयोग से वंचित कर दिया, यह एक बेईमान इरादा था, और परिणामस्वरूप उड़ान विमान की चोरी मानी गई।

किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को अस्थायी रूप से अपने पास रखना या कानूनी रूप से इसके हकदार व्यक्ति को संपत्ति से अस्थायी रूप से दूर रखना, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के तहत चोरी हो सकती है, और इस संबंध में यह अपराध अंग्रेजी कानून में "लार्सेनी" से भिन्न है जो स्थायी लाभ या हानि पर विचार करता है।

क्वीन-एम्प्रेस बनाम नागप्पा,(1890) एल.एल.आर. 15 रोम. 344 और क्वीन-एम्प्रेस बनाम श्री चर्न चुंगो (189) एल.एल.आर. 22 कैल. 1017, संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1955 की आपराधिक अपील संख्या 51

जोधपुर में सत्र न्यायाधीश की अदालत के 18 मई, 1953 के फैसले और आदेश से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 88, 1953 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के 22 अक्टूबर, 1953 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील 1953 की आपराधिक अपील संख्या 31 में।

अपीलकर्ता की ओर से जय गोपाल सेठी और आर.एस. नरूला।

प्रतिवादी की ओर से आर. गणपति अय्यर, पोरस ए. मेहता और आर. एच. ढेबर।

1957 फ़रवरी 11. न्यायालय का निर्णय जगन्नाथदास न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

अपीलकर्ता, के. एन. मेहरा और एक एमजेड फिलिप्स दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत दोषी ठहराया गया था और ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा अठारह महीने के लिए साधारण कारावास और 750 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। चार महीने का अतिरिक्त कार्यकाल. सत्र न्यायाधीश द्वारा अपील पर और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण पर उनके

खिलाफ दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है। हमारे समक्ष अपील अकेले अपीलकर्ता मेहरा की ओर से प्राप्त विशेष अनुमति द्वारा है।

मेहरा और फिलिप्स दोनों भारतीय वायु सेना अकादमी, जोधपुर में प्रशिक्षण पर कैडेट थे। अभियोजन एक ऐसी घटना के संदर्भ में है जो एक विमान की कथित चोरी के लिए असाधारण है, जो कि कमांडिंग ऑफिसर, अभियोजन गवाह 1 के साक्ष्य के अनुसार, अब तक कभी नहीं हुई है। कथित चोरी 14 मई, 1952 को हुई थी। फिलिप्स को कदाचार के आधार पर ठीक पिछले दिन, यानी 13 मई, 1952 को अकादमी से छुट्टी दे दी गई थी। मेहरा एक नेविगेटर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट थे। नेविगेटर का कर्तव्य केवल उपकरणों और मानचित्रों की सहायता से पायलट का मार्गदर्शन करना है। साक्ष्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि फिलिप भी नेविगेटर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था या नहीं। हालाँकि, यह सबूत है कि वह उड़ना जानता था। 14 मई 1952 को, फिलिप्स को अपनी छुट्टी के मद्देनजर ट्रेन से जोधपुर छोड़ना था। मेहरा को ओम प्रकाश नामक व्यक्ति के साथ अपने प्रशिक्षण के भाग के रूप में डकोटा में उड़ान भरनी थी; एक उड़ने वाला कैडेट. यह इस बात का सबूत है कि उन्हें इसकी जानकारी थी. फ्लाइट के उड़ान भरने का अधिकृत समय सुबह 6 बजे से 6-30 बजे के बीच था| प्रशिक्षण के तहत कैडेटों के पास आम तौर पर या तो स्थानीय उड़ानें होती हैं, जिसका अर्थ है हवाई अड्डे से लगभग 20 मील का उड़ान क्षेत्र या उनके पास क्रॉस-कंट्री अभ्यास हो सकता है और उस मार्ग के माध्यम से देश में उड़ान हो सकती है जिसके लिए वे विशेष रूप से अधिकृत हैं। उस सुबह माना जाता है कि मेहरा और फिलिप्स ने डकोटा नहीं, बल्कि हार्वर्ड एचटी 822 से उड़ान भरी थी। यह निर्धारित समय से पहले किया गया था, यानी, लगभग 5 बजे सुबह बिना किसी प्राधिकरण के और किसी भी औपचारिकता का पालन किए बिना, जो एक विमान के लिए आवश्यक शर्तें हैं -उड़ान। यह भी माना जाता है कि उसी दिन पूर्वाह्न में किसी समय वे भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 100 मील दूर पाकिस्तान में एक स्थान पर उतरे। यह एक जे सी कपूर के साक्ष्य में है, जो कराची में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के सैन्य सलाहकार थे, कि मेहरा और फिलिप्स ने 16 मई, 1952 की सुबह लगभग 7 बजे उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि वे वे अपना रास्ता भटक गए थे और जबरदस्ती एक खेत में उतर गए थे, और उन्होंने विमान वहीं छोड़ दिया। उन्होंने दिल्ली वापस जाने के लिए उनसे मदद की गुहार लगाई। इसके बाद कपूर ने उन दोनों को इंडियन नेशनल एयरवेज के

विमान से दिल्ली वापस भेजने की व्यवस्था की और हार्वर्ड विमान से जोधपुर भेजने की भी व्यवस्था की। जब वे 17 मई, 1952 को दिल्ली लौट रहे थे, तो विमान को जोधपुर में रोक दिया गया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत ट्रायल मजिस्ट्रेट की पूछताछ से पता चलता है, यह था कि मेहरा ने अपने सह-अभियुक्त फिलिप्स के साथ विमान हार्वर्ड एच टी 822 को चुरा लिया और उसके साथ पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी। बेईमान इरादा. बचाव, जैसा कि उसके उत्तरों से प्रतीत होता है, इस प्रकार था। मेहरा 14 मई की सुबह सामान्य समय पर हवाई अड्डे पर गए और फिलिप्स के साथ विमान से उड़ान भरी और उन्होंने कुछ देर तक उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया और दृश्यता कम हो गई और इसलिए उन्होंने अनुमान लगाकर विमान को वापस जोधपुर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कुछ समय तक वही जारी रखा जिसे वे वापसी यात्रा समझते थे; लेकिन पेट्रोल ख़त्म होने के करीब देख वे एक खेत में उतर गए, पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह पाकिस्तान क्षेत्र में है। इस बचाव को स्वीकार नहीं किया गया है और निचली अदालतों ने अभियोजन के मामले को साबित माना है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री सेठी ने इसे लगभग 22 वर्ष की आयु के एक युवा छात्र की ओर से एक विचारहीन शरारत के रूप में वर्णित करके घटना की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया, जो फ्लाइंग कैडेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। दंड संहिता के तहत कोई भी अपराध किया गया हो, चाहे उसमें शामिल नियमों और विनियमों का उल्लंघन कुछ भी हो। नीचे दी गई तीन अदालतों में से कोई भी, जिन्होंने इस मामले को निपटाया है, ऐसे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वास्तव में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने स्वयं ऐसा कोई बचाव नहीं किया है, इसे स्वीकार करना असंभव है। अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का अगला तर्क और जो अपीलकर्ता का बचाव भी प्रतीत होता है, वह यह है कि प्रशिक्षण के तहत एक कैडेट के रूप में वह उड़ान पर एक विमान लेने का हकदार था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ नियमों और विनियमों के अधीन और क्या सबसे अच्छी बात यह थी कि एक प्रशिक्षु द्वारा अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में एक अनधिकृत उड़ान के अलावा और कुछ नहीं था, जिसमें

वह अपना रास्ता भूल गया। उसे एक अज्ञात स्थान पर जबरदस्ती उतारना पड़ा और यह पाकिस्तान का क्षेत्र निकला। हालाँकि, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पाकिस्तान की उड़ान जानबूझकर की गई थी और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी उड़ान विमान की चोरी थी। इसलिए, तथ्य का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह जानबूझकर पाकिस्तान क्षेत्र में उड़ान थी। हम पर इस बात का बहुत दबाव डाला गया है कि ट्रायल कोर्ट इस कहानी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि उड़ान जानबूझकर पाकिस्तान के लिए की गई थी और इसलिए अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय के लिए इसके विपरीत खोजने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के सैन्य सलाहकार कपूर ने सबूत दिया कि जब अपीलकर्ता और फिलिप्स 16 मई, 1952 की सुबह कराची में उनसे मिले, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे दिल्ली के लिए उड़ान भरना चाहते थे। वहां के उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के उद्देश्य से। यह भी बताया गया कि न तो अपीलकर्ता और न ही फिलिप्स उड़ान में अपना कोई भी सामान अपने साथ ले गए। अब नीचे की अदालतों के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण पर उच्च न्यायालय और अपील पर सत्र न्यायाधीश दोनों अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले पर स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे। यह सच है कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि यह सुझाव कि अपीलकर्ता और फिलिप्स दिल्ली जाना चाहते थे, संभावना के दायरे से बाहर नहीं था। लेकिन इसने इस संभावना को केवल सज़ा तय करने के लिए ही प्रभावी बनाया. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट का यह भी विचार था कि उड़ान पाकिस्तान के लिए थी, जैसा कि उसके फैसले में निम्नलिखित अंश से पता चलता है।

"हालांकि रिकॉर्ड पर तथ्य लगभग निर्णायक रूप से इंगित करते हैं कि वे पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, संभावना के दायरे से परे अन्य सिद्धांत को खारिज करना असंभव है कि वे वहां के उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए दिल्ली जा रहे थे।"

इस संभावना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि दिल्ली सिद्धांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत पूछताछ के जवाब में अपीलकर्ता का बचाव नहीं था। यह स्पष्ट रूप से कपूर को यह प्रभावित करने के लिए दिया गया एक बहाना था कि उनकी उड़ान निर्दोष थी और उन्हें जोधपुर के बजाय दिल्ली वापस भेजने के लिए राजी किया गया था। हालाँकि, इस दलील का महत्व यह है कि यह सुझाव कि उड़ान एक

शरारत के माध्यम से या उड़ान सबक के हिस्से के रूप में थी, हालांकि विशेष उदाहरण में अनधिकृत, स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

हालाँकि, इस मामले पर ट्रायल कोर्ट के कुछ हद तक रुके हुए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमें साक्ष्यों के माध्यम से ले जाया गया है। मोटे तौर पर उन तथ्यों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा जिनसे, हमारी राय में, नीचे की अदालतों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि उड़ान पाकिस्तान के लिए थी, पर्याप्त कारण और औचित्य के बिना नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जिस विमान से अपीलकर्ता 14 मई की सुबह उड़ान भरने वाला था, वह डकोटा था लेकिन उसने हार्वर्ड विमान से उड़ान भरी। यह साक्ष्य में है कि यह सुबह 5 और 5-30 बजे के बीच किया गया था, यानी, निर्धारित समय से पहले। विमान को नियमित रूप से किसी अन्य उड़ान के लिए उपयोग करने के लिए हैंगर से बाहर लाया गया था। अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाह 12, हैंगर पर ड्यूटी पर मौजूद मैकेनिक को गलत बयानी देकर खुद ही इंजन चालू कर दिया कि उसके पास प्रभारी अनुभाग अधिकारी की अनुमति थी। उन्हें एक अन्य व्यक्ति, ओम प्रकाश नाम के एक फ्लाइट-कैडेट, के साथ उड़ान भरने का कार्यक्रम था। लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश के साथ उड़ान नहीं भरी, बल्कि एक डिस्चार्ज कैडेट फिलिप्स को, जो उड़ान भरना जानता था, अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। किसी भी विमान को उतारने से पहले, लड़ाई के लिए फ़्लाइट कमांडर द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। उड़ान प्राधिकरण पुस्तिका और फॉर्म नंबर 700 पर उस व्यक्ति को हस्ताक्षर करना होगा जिसे उड़ान के लिए विमान से उड़ान भरनी है। माना कि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है और कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया है। अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण यह है कि यह असामान्य नहीं है। हालाँकि, ये महज़ कोरी औपचारिकताएँ नहीं हैं बल्कि विमान के साथ-साथ उसमें उड़ान भरने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। अपीलकर्ता के इस सुझाव को स्वीकार करना असंभव है कि इन आवश्यक प्रारंभिक शर्तों का पालन किए बिना प्रशिक्षुओं को विमान से उड़ान भरने की अनुमति देना सामान्य बात है। अभियोजन पक्ष के लिए जिन अधिकारियों और गवाहों से पूछताछ की गई है, उनसे जिरह में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। यह साक्ष्य में है कि जैसे ही विमान के उड़ान भरने का पता चला, इसने अनिवार्य रूप से हवाई अड्डे में अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया और उसे वापस लाने के लिए विमान में बैठे लोगों को तुरंत रेडियो सिग्नल भेजे गए। एक बार हवाई अड्डे पर. लेकिन इन संकेतों पर ध्यान

नहीं दिया गया. अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण यह है कि विमान में रेडियो-टेलीफोन का पूरा उपकरण उनके पास नहीं था और उन्हें संदेश नहीं मिला। अपीलकर्ता का तो यहां तक कहना है कि विमान में कोई नक्शा या कम्पास या घड़ी भी नहीं थी। हालाँकि, हवाई अड्डे से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के साक्ष्य और उत्पादन से यह साबित होता है प्रदर्शनी पी-6, कि इस विशेष विमान को हैंगर से बाहर लाने से पहले परीक्षण किया गया था और यह उड़ान के योग्य था। यह विश्वास करना कठिन है कि सभी उपकरण ठीक हुए बिना उड़ान भरी गई होगी। यहां तक कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के सैन्य सलाहकार कपूर के साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता और फिलिप्स ने उन्हें बताया था कि विमान उड़ान योग्य था। इसलिए, इस संबंध में अपीलकर्ता का सुझाव स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें बताया गया है कि मौसम खराब होने और दृश्यता कम होने के कारण फोर्स-लैंडिंग के सुझाव के लिए साक्ष्य में कुछ समर्थन है। ऐसा हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि विमान को भारत-पाकिस्तान सीमा से आगे जाने के बाद जबरदस्ती क्यों उतारा गया। यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि अपीलकर्ता मेहरा अपने पाठ्यक्रम से किसी प्रकार का असंतोष महसूस कर रहा था और बदलाव पर विचार कर रहा था। सबूतों के मुताबिक, पाकिस्तान में रोजगार की तलाश करना उनके दिमाग में एक विचार था, हालांकि बहुत अनिश्चित तरीके से। इन सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता के खिलाफ यह माना जाना चाहिए कि एक उड़ान योग्य विमान को उड़ान के लिए ले जाया गया था और फिलिप्स जैसा व्यक्ति जो अच्छी तरह से उड़ान भरना जानता था और जिसे पिछले दिन छुट्टी दे दी गई थी, उसे जानबूझकर विमान में ले जाया गया था , हम इस बात से संतुष्ट हैं कि नीचे दी गई अदालतों का यह निष्कर्ष, कि पाकिस्तान के लिए उड़ान जानबूझकर की गई थी और आकस्मिक नहीं, उचित थी। इसलिए, इस मामले के तथ्यों को महज एक शरारत या एक अनधिकृत क्रॉस-कंट्री उड़ान के रूप में मानना संभव नहीं है, जिसके दौरान सीमा गलती से पार हो गई और बल-लैंडिंग अपरिहार्य हो गई।

यह आग्रह किया गया है कि यदि उड़ान का उद्देश्य पाकिस्तान जाना होता तो अपीलकर्ता और फिलिप्स ने कपूर से संपर्क नहीं किया होता और उनसे उन्हें वापस दिल्ली भेजने का अनुरोध नहीं किया होता। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उड़ान भरने के समय उनका इरादा नकारात्मक हो। हो सकता है कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें अपने उद्यम की अव्यवहारिकता का एहसास हुआ और उन्होंने इसे छोड़ दिया। यह देखा जा सकता है कि वे

वास्तव में तीन दिनों के लिए पाकिस्तान क्षेत्र में थे और हमारे पास उनके स्वयं के शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने 14 और 15 तारीख को कैसे समय बिताया। हालाँकि, यह हो सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जिनसे तथ्य न्यायालय उद्देश्य और इरादे का अनुमान लगाने की स्थिति में है और रास्ता भटकने की कहानी को आवश्यक उपकरणों के साथ विमान के उड़ान योग्य होने के संबंध में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह निष्कर्ष कि यह पाकिस्तान के लिए जानबूझकर की गई उड़ान थी, अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह सच हो सकता है कि वे अपना कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले गए थे, लेकिन संभवत: यह अचानक उड़ान भरने की योजना का हिस्सा था और इसमें पाकिस्तान के लिए खोजपूर्ण उड़ान के विचार को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, हमें नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों को स्वीकार करना चाहिए। उस दृष्टि से, विचार करने का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या साबित किए गए तथ्य भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के तहत चोरी हैं। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को लेने के लिए उस संपत्ति को स्थानांतरित करता है, उसे चोरी करना कहा जाता है ।" इसलिए, चोरी के कमीशन में (1) किसी व्यक्ति की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बाहर ले जाना, (2) बेईमानी के इरादे से संपत्ति को ले जाना शामिल है। इस प्रकार, (1) स्थानांतरण के समय व्यक्ति की सहमति का अभाव, और (2) ऐसा करते समय और उस समय बेईमान इरादे की उपस्थिति, चोरी के अपराध के आवश्यक तत्व हैं। नीचे के न्यायालयों में एक विवाद उठाया गया था, जिसे यहां भी दबाया गया है, कि इस मामले की परिस्थितियों में विमान को ले जाने के लिए सहमति निहित थी क्योंकि अपीलकर्ता एक कैडेट था, जिसे सामान्य स्थिति में अनुमति दी जाएगी प्रशिक्षण के उद्देश्य से विमान में उड़ान भरना। हालाँकि, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विमान को बाहर निकालने का ऐसे किसी प्रशिक्षण से कोई संबंध नहीं है। यह उस विमान से भिन्न विमान में था जो उस दिन अपीलकर्ता के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए था। इसे फ़्लाइट कमांडर के अधिकार के बिना और, नियत समय से पहले, फिलिप्स जैसे व्यक्ति की कंपनी में ले जाया गया था, जिसे छुट्टी दे दी गई थी, इसलिए उसे विमान में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जब उड़ान की अनधिकृत प्रकृति का पता चला तो वापस लौटने के संकेतों के बावजूद उड़ान जारी रखी गई। ऐसी स्थिति में सहमति का अर्थ लगाना असंभव है। हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का

मुख्य तर्क यह है कि इस मामले में किसी भी बेईमान इरादे का कोई सबूत नहीं है, उड़ान शुरू होने के समय ऐसे इरादे का तो बिल्कुल भी सबूत नहीं है। यह ठीक ही बताया गया है कि चूंकि चोरी की परिभाषा के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का स्थानांतरण ऐसे लेने के लिए होना चाहिए, "ऐसा" का अर्थ है "बेईमानी से लेने का इरादा", इसलिए इसे बाहर ले जाना बेईमानी के इरादे से होना चाहिए। तदनुसार, यह विचार करना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता के तहत "बेईमान" इरादे क्या शामिल हैं। संहिता की धारा 24 कहती है कि "जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है।" वह चीज़ बेईमानी से"। संहिता की धारा 23 इस प्रकार कहती है: "'गलत लाभ' संपत्ति के गैरकानूनी तरीकों से प्राप्त लाभ है, जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है। 'गलत हानि' गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति की वह हानि है जिसका खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार होता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ हुआ है जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से बनाए रखता है, साथ ही जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से अर्जित करता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान हुआ है जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी संपत्ति से बाहर रखा जाता है, साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से संपत्ति से वंचित किया जाता है।"

इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ लेते हुए, किसी व्यक्ति को बेईमान इरादे वाला कहा जा सकता है यदि संपत्ति लेने में उसका इरादा गैरकानूनी तरीकों से उस संपत्ति का लाभ उठाना है, जिसके लिए ऐसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है या नुकसान पहुंचाता है। गलत तरीकों से, उस संपत्ति का, जिसे खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। परिभाषा से यह और भी स्पष्ट है कि विचारित लाभ या हानि का पूर्ण अधिग्रहण या पूर्ण अभाव होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है यदि यह गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का अस्थायी प्रतिधारण है या संपत्ति को अस्थायी रूप से "बाहर रखना" है। कानूनी तौर पर हकदार व्यक्ति. यह स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के उदाहरण (1) में सामने लाया गया है और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त है जो बताते हैं कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता के तहत "चोरी" "लार्सेनी" से भिन्न है। अंग्रेजी कानून जो स्थायी लाभ या हानि पर विचार करता था। (देखें *क्वीन-एम्प्रेस बनाम श्री चर्न*

चुंगो, और क्वीन-एम्प्रेस बनाम नागप्पा). वर्तमान मामले में इसमें कोई उचित संदेह नहीं हो सकता है कि अनाधिकृत उड़ान के लिए अपीलकर्ता द्वारा हार्वर्ड विमान को बाहर ले जाने से वास्तव में अपीलकर्ता को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए विमान का अस्थायी उपयोग करने का मौका मिल गया है और विमान के मालिक को अस्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। , अर्थात, सरकार, अपने उद्देश्यों के लिए इसका वैध उपयोग, यानी, उस दिन भारतीय वायु सेना स्क्वाड्रन के लिए इस हार्वर्ड विमान का उपयोग। ऐसा उपयोग अनाधिकृत और विमान-उड़ान के सभी नियमों के विरुद्ध होने के कारण स्पष्ट रूप से गैरकानूनी तरीकों से लाभ या हानि था। इसके अलावा, गैरकानूनी पहलू इस तथ्य से उजागर होता है कि यह पाकिस्तान में किसी स्थान के लिए उड़ान के लिए था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि निचली अदालतों ने सहमति के अभाव को बेईमानी माना है और स्पष्ट रूप से इस बात की सराहना नहीं की है कि ये दोनों चोरी के अपराध के अलग और आवश्यक घटक हैं। हालाँकि, सही स्थिति यह है कि अनधिकृत उड़ान की सभी परिस्थितियाँ सहमति की अनुपस्थिति और उन साधनों की गैरकानूनीता दोनों के निष्कर्ष को उचित ठहराती हैं जिनके द्वारा विमान के उपयोग से अस्थायी लाभ या हानि हुई है। इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को गलत लाभ और सरकार को गलत नुकसान हुआ है।

इसलिए, विचार के लिए एकमात्र अतिरिक्त प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का गलत लाभ या हानि जानबूझकर किया गया था और यदि हां, तो क्या उस समय ऐसा इरादा माना गया था जब विमान ले जाया गया था। यदि, जैसा कि पहले ही पाया गया है, जिस उद्देश्य से उड़ान भरी गई थी वह पाकिस्तान जाना था, और यदि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसे विमान को उड़ान के लिए प्रारंभिक रूप से बाहर ले जाने से संबंधित विभिन्न नियमों का उल्लंघन शुरू में ही किया गया था , इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है, जैसा कि नीचे की अदालतों ने किया है, कि बेईमान इरादा, यदि कोई हो, बिल्कुल शुरुआत में था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता की स्थिति में एक व्यक्ति ने अधिकृत उड़ान शुरू की और उसके दौरान बेईमान उद्देश्य के लिए इसका फायदा उठाया। ऐसे मामले में, प्रारंभिक बेईमान इरादे का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। हालाँकि, सवाल यह है कि क्या गलत लाभ और गलत हानि जानबूझकर की गई थी। यह आग्रह किया जाता है कि दंड संहिता विभिन्न स्थानों पर किसी विशेष परिणाम को उत्पन्न करने के इरादे और किसी विशेष परिणाम को

उत्पन्न करने की संभावना के ज्ञान के बीच जो सुप्रसिद्ध अंतर करती है, उसकी सराहना नहीं की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि निर्णय किए गए मामलों में बताया गया है कि यह कहावत कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्राकृतिक परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, एक कानूनी कल्पना है जिसे भारतीय दंड संहिता में दंडात्मक परिणामों के लिए मान्यता नहीं दी गई है। *(वुलप्पा बनाम भीमा रो देखें).* अब उचित मामले में इन भेदों के बारे में जो भी कहा जाए, इस मामले में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, हालांकि उड़ान का अंतिम उद्देश्य पाकिस्तान जाना था, उस उद्देश्य के लिए विमान का उपयोग और अनधिकृत और इसलिए अपीलकर्ता को उस उपयोग से गैरकानूनी लाभ और उसके वैध उपयोग से सरकार को होने वाली हानि को केवल जानबूझकर माना जा सकता है। यह किसी अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एक वैध निष्कर्ष के रूप में है। इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जो तथ्य साबित हुए हैं वे चोरी हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, हमारी राय में, सही है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने बहुत ज़ोर देकर आग्रह किया है कि मामले की परिस्थितियाँ पर्याप्त सज़ा देने की आवश्यकता नहीं रखती हैं।(सरल) अठारह महीने की कैद. उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अपीलकर्ता, जो अब जमानत पर है, लगभग एक वर्ष की सजा काट चुका है और हम पर दबाव डालता है कि मामले में न्याय के हितों को, तारीख से चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं है। अपराध के घटित होने पर, अपीलकर्ता की स्थिति के एक युवक को शेष सजा काटने के लिए वापस जेल भेजा जाना चाहिए। हमने सरकार की ओर से पेश वकील से पता लगाया है कि अपीलकर्ता पहले ही 11 महीने और 27 दिन की सजा काट चुका है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें यह भी सूचित किया है कि अपीलकर्ता एक विचाराधीन कैदी के रूप में लगभग ग्यारह महीने तक न्यायिक हिरासत में था। मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए, हम इस बात से सहमत हैं कि न्याय के हित में उसे वापस जेल भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, अपीलकर्ता केएन मेहरा की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम उसके खिलाफ कारावास की सजा को पहले ही पूरी की जा चुकी अवधि तक कम कर देते हैं। जुर्माने

की सजा और इसका उल्लंघन करने पर कारावास की सजा बरकरार रहेगी। वाक्य में इस संशोधन के साथ अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज कर दी गई, और सजा संशोधित की गई।

के. एन. मेहरा बनाम राजस्थान राज्य

चन्द्र कान्त शुक्ल की देखरेख में शशि प्रभा द्वारा अनुवादित